प्रकाशित: 11 अप्रैल 2018 को दैनिक जागरण में प्रकाशित-

चंपारण से स्वच्छाग्रह की गूंज, साढ़े तीन साल में हुआ ये कमाल

अलका आर्य

सौ साल पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी और चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मील का पत्थर साबित हुआ। 2017-18 चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समापन को 'सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह' के रूप में मना रही है। इसी उपलक्ष्य में 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंपारण में देशभर के करीब चार लाख स्वच्छाग्रहियों, जो खुले में शौच से मुक्ति दिलाने (ओडीएफ) के लिए काम कर रहे हैं, को संबोधित किया। इनमें से 20,000 चंपारण में मौजूद थे, जबकि अन्य स्वच्छाग्रही मुल्क के विभिन्न हिस्सों से सोशल मीडिया व अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़े थे।

साफसफाई ईश्वर भक्ति के बराबर-

सरकार की मंशा महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की तर्ज पर स्वच्छाग्रह को देशभर में चलाने की है। दरअसल गंदगी मुक्त भारतस्वच्छ भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और वह - मासिक कार्यक्रम'मन की बात' में स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं से लोगों को अवगत कराते रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था कि साफसफाई ईश्वर भक्ति के बराबर है। उन्होंने स्वच्छ भारत - का सपना देखा था और वे चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक स्वच्छ भारत के निर्माण में अपना कीमती योगदान दें। स्वच्छता के इसी संदेश को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए 'सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह' मुहिम की शुरुआत की गई।

स्वच्छ बिहार अभियान चला रही नीतीश सरकार

चंपारण स्वच्छाग्रह में पूरे देश से करीब दस हजार स्वच्छाग्रहियों को बिहार आमंत्रित किया गया, जिन्होंने (3-10 अप्रैल के बीच) बिहार सूबे के ही स्थानीय दस हजार स्वच्छाग्रहियों के साथ मिलकर प्रदेश की जनता को ओडीएफ के लिए प्रेरित किया। अलग-अलग राज्यों से आए स्वच्छाग्रहियों ने बिहार के स्थानीय स्वच्छाग्रहियों के साथ मिलकर मुहिम चलाई और खुले में शौच से मुक्ति का स्थायित्व बनाए रखने के लिए समुदाय आधारित स्वच्छता रणनीति अपनाते हुए सामूहिक व्यवहार

परिवर्तन पर काम किया। बिहार अविकसित सूबा है और सूबे को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार स्वच्छ बिहार अभियान चला रही है। इस अभियान को केंद्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा राज्य संपोषित लोहिया स्वच्छता योजना के प्रावधानों के तहत पूरा किया जा रहा है। स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 1.2 करोड़ ग्रामीण परिवारों को शौचालय उपलब्ध करवा कर बिहार को दो अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच से मुक्त कराने का लक्ष्य है। एक मार्च, 2018 तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार के करीब 41 फीसद ग्रामीण परिवारों की स्वच्छता सुविधा तक पहुंच थी।

अब तक 15 राज्य ओडीएफ घोषित

राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव परमेश्वरन अय्यर के अनुसार तीन अप्रैल तक देश के 3.44 लाख गांव, 360 जिले, 15 राज्य व तीन केंद्र शासित राज्य ओडीएफ हो चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि दो अक्टूबर, 2019 तक देश ओडीएफ का शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लेगा। - सचिव अय्यर के अनुसार जो गांव ओडीएफ घोषित हो गए हैं, उनमें पाइप जल की सुविधा मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल है। ऐसा नीतिगत फैसला लिया गया है।

साढ़े तीन साल में हो गया कमाल

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने साढ़े तीन साल पहले दो अक्टूबर, 2014 को दो अक्टूबर, 2019 तक भारत को 'स्वच्छ भारत' बनाने का एलान किया था। यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सैनिटेशन अभियान है। अक्टूबर 2014 तक 55 करोड़ लोग खुले में शौच करते थे, 38.7 फीसद लोगों की पहुंच स्वच्छता सुविधा तक थी, पर तीन अप्रैल, 2018 तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 55 करोड़ लोगों वाला आंकड़ा 20 करोड़ रह गया है और टॉयलेट कवरेज 38.7 से बढ़कर 80.53 प्रतिशत हो गई है।

77 फीसद टॉयलेट का 93 फीसद इस्तेमाल

एक सवाल अक्सर चर्चा में रहता है कि शौचालय बन भी गया तो क्या गांरटी है कि घरसमुदाय /परिवार- के लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। स्वतंत्र जांच एजेंसी के हालिया सर्वे के अनुसार6000 से अधिक गांवों में 90,000 घरों का सर्वे किया गया और पता चला कि ग्रामीण टॉयलेट कवरेज 77 प्रतिशत है और शौचालयों का इस्तेमाल 93.4 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के स्वच्छाग्रही हरिओम इस बाबत गांव की बसावट व सामाजिक तानेबाने पर जोर देते हैं। हरिओम का कहना है कि गांव में रिश्ते बनाकर ही शौचालय का - इस्तेमाल बहुत हद तक सुनिश्चित किया जा सकता है। रिश्तों के जरिये गांववासियों को शौचालय के इस्तेमाल के लाभ बताए जा सकते हैं और स्वच्छाग्रही इस मुहिम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। गरीबों तक स्थाई स्वच्छता सेवाएं मुहैया कराना स्वच्छ भारत अभियान की एक महत्वपूर्ण कसौटी है। साफ-सफाई, स्वच्छता की कमी विशेष तौर पर गरीब समुदायों व संवेदनशील बच्चों को प्रभावित करती है।

गंदगी से होता है करोड़ों का नुकसान

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में पांच साल से कम आयु के 1,17,000 बच्चे डायरिया के कारण मर गए थे। डायरिया से उनके शरीर में पोषक तत्वों को संपूर्ण जिंदगी के लिए धारण करने की क्षमता को नुकसान पहुंचता है। यूनिसेफ इंडिया वॉश चीफ निकोलस असवर्ट ने यूनिसेफ के सर्वे के हवाले से बताया कि गंदगी होने व शौचालय न होने के कारण प्रति घर दवाओं पर सालाना 50,000 रुपये खर्च करता है। इसमें समय की कीमत, मेडिकल पर होने वाले खर्च आदि शामिल हैं। यह सर्वे दस हजार भारतीय परिवारों पर कराया गया था और अध्ययन यह भी बताता है कि सैनिटेशन में सुधार पर निवेश किए गए एक रुपये से 4.3 रुपये की बचत होती है।

सरकार ले रही स्वच्छाग्रहियों की मदद

दरअसल स्वच्छता एक दैनिक कर्म है, जिसे हर इंसान को मन से करना चाहिए, क्योंकि इसका पहला लाभार्थी वही होता है, उसका परिवार व समुदाय अगली कड़ी हैं। सरकार का काम हर देशवासी के लिए स्वच्छ सेवाएं मुहैया कराना है, आसानी तक पहुंच को संभव बनाना है। स्वच्छ सेवाओं के दायरे को बढ़ाने व शत प्रतिशत इस्तेमाल के लिए सरकार स्वच्छाग्रहियों की मदद ले रही है। देशभर में इस समय-4.2 लाख स्वच्छाग्रही पंजीकृत हैं व सरकार का लक्ष्य मार्च 2019 तक इस संख्या को बढ़ाकर 6.5 लाख करना है। हर गांव में कम से कम एक स्वच्छाग्रही होना चाहिए, यह सरकार का लक्ष्य है। चंपारण से सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की गूंज को पूरी दुनिया सुनेगी।

(लेखिका सामाजिक मामलों की जानकार हैं)